

सम्पादकीय

तात्कालिक हितों से आगे

चाहे संयुक्त राष्ट्र के अलग-अलग मंचों का उपयोग करने का सवाल हो या विभिन्न मित्र देशों से बातचीत का- भारत ने हर मौके का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने की कोशिश में किया है कि अफगानिस्तान दुनिया भर में तबाही फैलाने का नया केंद्र न बने और न ही वहां के नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन बिताने में कोई स्थायी बाधा खड़ी हो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के सत्र को संबोधित करते हुए भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान इस तथ्य की ओर खीचा कि अफगानिस्तान में सुरक्षा और मानवाधिकार का कितना बड़ा मसला खड़ा हो रहा है। उसने हर हाल में यह सुनिश्चित करने की जरूरत बताई कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन अन्य देशों के खिलाफ न कर सकें। गौर करने की बात है कि जहां इस क्षेत्र के कुछ अन्य देश अपने नजरिए को अपने संकीर्ण और तात्कालिक हीतों तक सीमित रखते हुए तालिबान से करीबी बनाने में लगे हुए हैं, वहीं भारत खुद को संयत रखते हुए न केवल अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, बल्कि देश दुनिया की वृहत और दूरगामी चिंता को स्वर दें रहा है।

चाहे संयुक्त राष्ट्र के अलग-अलग मंचों का उपयोग करने का सवाल हो या विभिन्न मित्र देशों से बातचीत का- भारत ने हर मौके का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने की कोशिश में किया है कि अफगानिस्तान दुनिया भर में तबाही फैलाने का नया केंद्र न बने और न ही वहां के नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन बिताने में कोई स्थायी बाधा खड़ी हो। कुछ हलकों से यह सवाल उठाया गया है कि भारत सरकार अफगानिस्तान के सवाल पर कुछ बोल क्यों नहीं रही। लेकिन यह समझे जाने की जरूरत है कि अफगानिस्तान में अभी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और यह साफ नहीं हो रहा है कि वहां आखिरकार स्थितियां क्या आकार लेने वाली हैं। तालिबान ने अपनी तरफ से कुछ पदों पर नियुक्तियों की घोषणा जरूर की है, लेकिन सरकार अभी वहां बनी नहीं है। देखना होगा कि तालिबान अकेले अपनी सरकार घोषित करते हैं या हामिद करजई जैसी किसी शख्सियत को प्रमुख बनाते हुए अपने प्रभाव वाली सरकार बनाते हैं या विभिन्न समूहों को मिला-जुलाकर कोई संयुक्त राष्ट्रीय सरकार बनाई जाती है। इसके बाद ही संबंधित सरकार को लेकर कोई रुख कायम किया जा सकता है। फिलहाल पहली जरूरत यही है कि जो लोग वहां फँसे हुए हैं और निकल कर भारत आना चाहते हैं, उनके सुरक्षित निकल आने की व्यवस्था की जाए। यह काम लगातार किया जा रहा है। यह भी अच्छी बात है कि सरकार ने गुरुवार को अफगानिस्तान के सवाल पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अपने देश में विदेश नीति से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर राजनीतिक सर्वमान्यता की परंपरा रही है। इस परंपरा को कायम रखते हुए विपक्ष को विश्वास में लेने की सरकार की यह पहल सराहनीय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सर्वदलीय बैठक से उभरीं भारत सरकार की नीतियां न केवल अफगानिस्तान को झंझागत के मौजूदा दौर से निकलने में मदद करेंगी बल्कि वहां की नई सरकार को भारत की चिंताओं का सम्मान करने को भी प्रेरित करेंगी।

व्यापारी दौर में अध्यापन की चुनौती

डॉ. गिरीश्वर मिश्र

मानव शिशु को मनुष्य बनाने में शिक्षा को भासका सभी सभ्य समाजों में स्वीकृत है और इसे सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिए शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ। ये संस्थाएं समाज की उत्तरि के साथ बदलती ही रहीं ताकि ज्ञान में आ रहे बदलाव को शामिल करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल नई पीढ़ी तैयार ही सके। समाज के लिए जरूरी कारोबार चलाने के लिए प्रशिक्षित लोगों (मानव संसाधन !) की जरूरत पड़ती है। इस तरह अपनी उपादेयता के चलते शिक्षा संस्था समाज और राज्य की अहं जिम्मेदारी बन गई कि वह इनके भरण - पोषण की व्यवस्था करे। पर शिक्षा की संस्था स्वायत्त रखी गई जहां गुरु और शिक्षक बिना किसी दबाव के स्वाधीन रूप में ज्ञान-सृजन और उसके विस्तार का काम करते रहें। इस तरह शिक्षा- कार्य की परिधि का निर्धारण गुरु जन तथा विवेक द्वारा होता था, जिन्हें परम्परा और समकालीन परिस्थिति दोनों विज्ञान होता था। वे शिक्षा देते हुए समाज के भविष्य को संवरने वाला दायित्व निभाने के संकल्प के साथ अपना कार्य करते थे। प्राचीन गुरुकुमारों के समय से जो छवि गढ़ी गई और लोक जीवन में प्रतिष्ठित हुई, उसके गुरु से बहुत सारी अपेक्षाएं जोड़ दीं और उसे आचरण के मानक के रूप में स्थापित कर दिया।

नैतिकता, निस्पृहता, विवेकशीलता, दक्षता और उदारता के सटुपु के साथ अध्यापक को आदर्श या मॉडल के रूप में देखा जाने लगा समाज की यही आकांक्षा रही कि गुरु स्वयं में एक संस्था बन कर बिन किसी स्वार्थ के शिक्षा के उच्चयन में लगा रहे। गुरु को यदि रचनाकार कबीर के शब्दों में कुम्हार !) कहा गया तो उसका आशय यही था कि अपने हस्तक्षेप द्वारा वह एक अनगढ़ विद्यार्थी में अपूर्व कुशलता पैदा कर पात्रता ले आता है। तब विद्यार्थी स्नातक घोषित होता है और दीक्षांत त

जलभराव : शहरों-क आलोक शुक्ला

आलोक शुक्ला

शहरों-कस्बों के आसपास पहले खेती की जमीनें होती थीं। छोटे-बड़ा लालब होते थे। इनकी संख्या अब घट गई है और अतिक्रमण के कारण दिन-प्रति दिन इनका क्षेत्रफल घट रहा है। जल संग्रहण करने वाले जगहों का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा तो पानी आखिर जाएगा कहां या याद रखना होगा कि पानी अपना रास्ता खुद ढूँढ़ लेता है। बारिश व मौसम बड़ा ही खुशनुमा होता है। इसे सूजन का मौसम भी कहते क्योंकि यह अनेक कीटों एवं पशु-पक्षियों का प्रजनन काल है। बारिश धरती की प्यास बुझती है। किसान खेती-बाड़ी के कामों में लग जाते हैं धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। जब बारिश अपने पूरे जोर पहोती है तो महानगरों से लेकर बड़े-छोटे शहरों और बड़े कस्बों के लोग जलभराव की मुसीबत का सामना करने लगे हैं। लोग बरसात खत्म होते तक जलभराव से परेशान रहते हैं। जलमग्न शहर, पानी में डूबी रेत, पटरियां, ठप पड़ा सड़क यातायात और महानगरों व बड़े-बड़े शहरों कई फृट तक पानी में डूबी सड़कों का मंजर आम हो गया है। दिल्ली मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों के अलावा पटना, अंबाला अहमदाबाद सरत काजपर भोपाल नागपर रायपर जैसे कई शहर

तालिबानी शासन में अफगानिस्तान और भारत में संबंध जरूरी

डॉ. हनुमंत यादव

तालिबान के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अब्बास स्टेनकजर्ड ने दावा किया है कि उनकी सरकार भारत के साथ अफगानिस्तान के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध जारी रखना चाहेगी। जम्मू व कश्मीर को अनावश्यक आतंकवादी हिंसा से बचाने के लिए भी अफगानिस्तान और भारत में राजनीतिक संबंध के साथ-साथ आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध पुनः बहाल करने लिए शीघ्र प्रयास भारत के हित में अधिक जरूरी है। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में प्रवेश करते समय यह कल्पना भी नहीं की होगी कि निर्वाचित राष्ट्रपति अशरफ गनी पलायन करके कब्जे के लिए राजधानी निष्कंटक छोड़ जाएंगे। राजधानी काबुल पर कब्जा जमाते ही तालिबान ने अमेरिका को स्मरण कराना था कि उसको हर स्थिति में 31 अगस्त से पहले काबुल छोड़ देना है। 26 अगस्त को आईएसआईएस.के. आतंकी समूह के तीन विस्फोटों से काबुल विमानतल क्षेत्र दहला दिया, इसमें 13 अमेरिकी कमांडो सहित 169 व्यक्ति मारे गए थे और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत का बदला लेते हुए 28 अगस्त की रात्रि को नानगाहर में द्वौन द्वारा बमबारी करके 26 अगस्त को बमबारी करने वाले आईएसआईएस.के. आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिका ने 29 अगस्त की संध्या आईएसआईएस.के. विस्फोटक से भरे गहन और 30 अगस्त को प्रातः संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर राकेटों से हमला किया। अमेरिका को काबुल छोड़ने में अभी दो दिन बाकी हैं। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि 28 अगस्त को ही काबुल से अपने देशों की ओर से प्रस्थान कर गए। संयुक्त राज्य अमेरिका का राजनियक स्टाफ एवं सैनिक दस्ते 31 अगस्त तक अमेरिका चले जाएंगे किंतु वह सैनिक एवं असैनिक चल व अचल साज-सामान अफगानिस्तान में ही छोड़ता जा रहा है। इसमें ऐसी उच्च प्रौद्योगिकी युक्त युद्ध सामग्री व गहन भी शामिल हैं जिनके परिचालन हेतु उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है जिनका मिलना अफगानिस्तान में संभव नहीं है। अब तो इन सब पर तालिबान सरकार का स्थापित होने जा रहा है। फिलहाल

तालिबान सरकार ने प्रशासन को चलाने के लिए कार्यवाहक मंत्रियों की नियुक्तियां की हैं। राष्ट्रपति एवं अन्य नियमित पदों पर नियुक्तियां 31 अगस्त के बाद होंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हर दिन किसी न किसी समाचार माध्यम में उनके वक्तव्य आते रहते हैं। वे पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का सच्चा मित्र बताते हुए दावा करते हैं कि जब भी पाकिस्तान से सहयोग मांगा जाएगा वे सच्चे मित्र के नाते पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।

फिलहाल तालिबान की सबसे बड़ी समस्या पंजशीर प्रान्त पर कब्जे की है। यही अफगानिस्तान का एकमात्र प्रान्त है जिस पर तालिबान के लड़ाके कब्जा नहीं कर सके हैं। अफगानिस्तान के स्वघोषित कार्यवाहक राष्ट्रपित के नेशनल रेजिस्टरेस फोर्स के विरोध के कारण तालिबान का इस प्रान्त पर कब्जा करना बहुत कठिन है। पंजशीर खनिज संपदा में धनी पर्वतीय घाटी है, इसके मैदानी प्रवेश द्वारा तक आसान होने के कारण पहुंचा जा सकता है, किंतु घमावदार पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन उतना ही कठिन है। यही कारण है कि अफगानिस्तान के शासकों ने इस घाटी के लिए सैनिक सर्वेक्षण से परहेज किया है। वे अपने शासनकाल में पंजशीर को पुस्तैनी प्रभारियों को सौंपते जाते थे। मेरे विचार में तालिबान के लिए यह अधिक बेहतर होगा कि वह पहले अफगानिस्तान पर सैनिक प्रशासन के साथ-साथ नागरिक प्रशासकों की नियुक्ति करके कुछ माह में शेष अफगानिस्तान में स्थिति सामान्य बनाने का प्रयास करे। तालिबान को अफगानिस्तान में नागरिक प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि की सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। अफगानिस्तान को संपत्तियों के क्रय एवं भुगतान हेतु 21 जून 2021 तक 382 मिलियन डॉलर की एस.डी.आर. मिली हुई थी। अब तालिबान सरकार को उस सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। इसी प्रकार अन्य बड़ी बैंकिंग संस्थाओं द्वारा दी गई सुविधा तालिबान सरकार को नहीं मिल पाएगी। इस कारण सितंबर महीने से ही तालिबान सरकार को नागरिक प्रशासन चलाने के लिए भुगतान करने की समस्या आने वाली है। पाकिस्तान सरकार आज ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकिंग संस्थानों के माध्यम से इस समस्या का निराकरण करवा सके। वर्तमान में तालिबान का दूसरा मित्र चीन है। वर्तमान स्थिति में तालिबान सरकार को चीन की देखने और प्रतीक्षा करने की नीति अपनाएंगे उसके बाद ही नई सरकार को मान्यता देंगे। इन देशों के इंतजार करने का एक बड़ा कारण यह था कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में अफगानिस्तान सरकार के निर्वाचित कार्यवाहक राष्ट्रपित अमरललाह सालेह ने सभी देशों को संदेश भेजा था कि निर्वाचित सरकार तालिबानी आक्रमणकारियों का मुकाबला कर रही है। इसलिए मुस्लिम देशों ने भी कोई निर्णय नहीं लिया है, राजनैतिक स्थिति स्पष्ट होने पर वे निर्णय लेंगे। अफगानिस्तान में आईएसआईएस के द्वारा अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में विस्फोट करने से स्थिति ने अनावश्यक भ्रम पैदा कर दिया है। जिस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी बिदाई लेकर सैनिक वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान का वित्तीय संकट भी धीरे-धीरे सुलझ जाएगा। धीरे-धीरे मुस्लिम देशों की मान्यता नई सरकार को मिलने लग जायेगी। नई सरकार इस्लामिक कायदे के अनुसार युवकों और युवतियों की सह-शिक्षा पर रोक लगाएगी। एक तालिबान आधिकारी के अनुसार पुरुषों के पदों पर स्त्रियों की अनावश्यक नियुक्तियों के कारण पुरुषों में होने वाली अनावश्यक बेरोजगारी की स्थिति पैदा नहीं होने देगी। काबुल से विमान सेवा पुनः प्रारंभ हो जायेगी। अफगानिस्तान इंडियन मिलिट्री एकेडेमी में प्रशिक्षण प्राप्त तालिबान के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अब्बास स्टेनकर्जई ने दाव किया है कि उनकी सरकार भारत के साथ अफगानिस्तान के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध जारी रखना चाहेगी। जम्मू व कश्मीर को अनावश्यक आतंकवादी हिंसा से बचाने के लिए भी अफगानिस्तान और भारत में राजनीतिक संबंध के साथ-साथ आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध पुनः बहाल करने लिए शीघ्र प्रयास भारत के हित में अधिक जरूरी है।

कोरोना ने हमें लोगों से बात करना भुला दिया?

ਪ੍ਰਾਤਿ ਦੁਬੈ

वह बालकनों में रिकलाइनर कुसों पर लेटो धूप सेंक रहा था। हालांकि मेरे लिए अब भी बाहर सर्दी का मौसम चल था। लेकिन यहां डेनिशा (डेनमार्क के स्थानीय निवासी) लोगों के लिए सूरज की इनायत की खातिर 16 डिग्री ही काफी है। जब नपी-तुली सूरज की किरणें मिलती हैं तो काम चलाना ही पड़ता है। मैं उसका घेरा ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन हाथ-पैर देखकर अंदाजा लगा लिया कि यह लोकल डेनिश ही है। स्किन का रंग पीलापन लिए हुए सफेद था, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में फोन। बालकनी का रुप-रंग भी बदला-सा लग रहा था, जैसे कि मकांवर मिल गया हो। कई सारे फूलदान और रंगबिरंगी रोशनीवाली लड़ियां मैंने नोटिस कीं। जोनस की बालकनी को मैंने कभी ऐसा सजानहीं देखा। शायद यह जोनस की मेहमान या उसकी गर्लफ्रेंड हो। पहले कभी नहीं देखा इस लड़की को यहां। खैर मैं तैयार थी अपनी रनिंग के लिए इसलिए बिना हाय-हेलो किये वहां से चलती बनी। पूरे 10 दिन बाद अपना क्वारंटीन कारावास पूरा करके घर से बाहर निकली थी। मौसम थोड़ा ठंडा था लेकिन हवा की ताज़गी अपने सीने के भीतर भरने को मैं न जाने कब से बेताब थी। लगभग 5 महीने अपने देश में बिताकर वापस

लोटी थी। इस बार अचार और मसालों के साथ उदासी और मायूसी भौंगी साथ ले आई थी। इस कोरोना काल में वहाँ जो देखा और महसूस किया वह मन पर गहरे-काले बादलों-सा छाया था।

दिसंबर के महीने में जब यहां से गई थी तो सब कुछ ग्रे रंग में रंग था और जब वापस आयी तो आस-पास हरियाली के निशान दिखने लगे थे। घर से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा ग्रीन एरिया है। यहां अक्सर हवा वाँक या रनिंग के लिए आते हैं। इसी एरिया के कुछ हिस्सों में सेमेटी भी है यानी एक के बाद एक लाइन से बनी लोगों की कब्रें हैं। पास ही मैं एक तालाब और चर्च भी है। जीवन और मृत्यु एक साथ। कभी-कभार लोग तालाब के पास पिकनिक करते दिख जाते हैं तो कभी वहीं थोड़ी ही दूरी पर लोग 3-4प्ने प्रियजनों की समाधि पर फूल चढ़ाते दिखते हैं। जो यह लोग इन समाधियों में सोये हैं वे क्या कभी इस रास्ते पर भी दौड़े होंगे क्या उन्होंने कभी इस तालाब के पास पिकनिक मनाई होगी? दौड़ते हुए मेरी नज़र उन सेमेटीज पर जाती है। पेड़ों पर आए नए नवेले हरे पत्ते घासों पर सितारों-सी बिखरी अनगिनत सफेद डेढ़ी और चेरी के गुलाबों कोमल फूल मन में फैले ग्रे रंग को रंगने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी न जाने क्यों मन उदासी और डर के घेरे में जी रहा था। कोरोना काल में शायद सभी का यही हाल था। मैं अपनी रनिंग से वापस लौटती हूँ, देख वह अब भी वहीं लेटी थी। और शायद यह उसकी तीसरी या चौथी

स की चुनौती

इस तरह मृक्त करने की जगह शिक्षा बंधनों में बांधने वाली होती जा रही है। इस पर्याप्ति को सामाजिक परिवर्तन का स्वाभाविक अंग मान कर अंगीकार कर लेना समाज के लिए हितकर न होगा। शिक्षा चाहे जैसी हो, एक हस्तक्षेप होती है और समाज में दृष्टिगत प्रवृत्तियों को उसके अलग कर नहीं समझना चाहिए।

शिक्षा और शिक्षक देश की नीति की वरीयता सूची में अभी तक पिछड़ते रहे हैं। वर्तमान सरकार इस दिशा में ज्यादा सक्रिय हुई है। नई शिक्षा नीति जिस भारत केंद्रित शिक्षा की बात कर रही है और जिसका तरह छात्रों की दक्षताओं और प्रतिभाओं पर ध्यान देने के लिए अवसरों का बनाने के लिए सोच रही है, उसका ताना - बाना अध्यापकों के इर्द गिरावट की बुना जा सकेगा। उसके लिए अध्यापकों का प्राशिक्षण और दृष्टिकोण भी बदलना होगा। यह आवश्यक होगा कि जमीनी हकीकत बदली जाए और इसके लिए प्रतिबद्ध हो कर कार्य किया जाय।

आर इसके लिए प्रातबद्ध हो कर काय लिया जाय।

बिगड़ जाते हैं हालात

स्थानीय नेता और पार्षद अपने लोगों को इन नालियों के निर्माण, मरम्मत और सफाई का ठेका दिलवा देते हैं। नेताओं-अफसरों की कमीशनखोर्स और भ्रष्टाचार में सहभागिता के कारण प्रभारी अधिकारियों, ठेकेदारों की अनुभवहीनता घटिया दर्जे के निर्माणों को अनदेखा कर देते हैं। इस सब कारण स्थिति को बदतर बना देते हैं।

राजनीतिक दलों की अनुशासा पर शहर की भौगोलिक स्थिति और विकास की ज़रूरतों को समझे बिना भारी-भरकम बजट से होने वाले रुप अनियोजित विकास कार्य जलभाराव के मुख्य कारण होते हैं। मुंबई यह साल बृहन्मुंबई महानगरपालिका मानसून आने के पहले जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है लेकिन चंद घंटों की बारिश ही पूरे मुंबई की दशा बदल कर व्यवस्था की पोल खोल देती है। कई स्थानों पर गटर के ढक्कन खुले रहते हैं जिनकी वजह से मुंबई में हर साल कई जानें जाती हैं। बारिश और जलभाराव के कारण मुंबई में पुराने मकानों के गिरने से भी कई लोग जान से हात्या थे बैठते हैं। हादसों में हुई मौतों पर एक-दो दिन हगामा होता है और फिर वे हालात हो जाते हैं। दिल्ली में भी हालात किसी से छिपे नहीं हैं। पहले यहां सड़कों के किनारे पैदल चलने की जगह में टाईल्स लगी। बाद में इंटरलॉक टाईल्स लगाई गई जिससे पानी जमीन के भीतर जा सके। अब हर जगह कांक्रीट की सड़कें बन रहीं हैं जिनसे पानी जमीन के अंदर नहीं जाता और जल भरात की समस्या पैदा हो रही है।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह काई भूखा न रहे

डॉ अश्वनी कुमार मल्होत्रा

यह घटना आज से करीब 45 वर्ष पूर्व की रही होगी, जब मैं धनबाद के पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का छात्र था। उन्हीं दिनों हमारे एक सहपाठी, जिसकी शादी कुछ महीने बाद होनी तय थी, ने अपनी मंडली के दोस्तों, जिनमें भी शामिल था, से कहा की, चलो कलकत्ता घूलते हैं, मुझे शादी के लिए कुछ सामान खरीदना है, तो हम सहर्ष तैयार हो गए। धनबाद से कलकत्ता रेल सफर द्वारा अनुमानित 4 घंटे का रास्ता था तो एक ही दिन में आ जा सकते थे। शॉपिंग करते करते हुए हम बंगाली व्यंजनों और मिष्ठान का भी आनंद लेते रहे। अब बंगाली मिष्ठान की बात हो तो कोई कैसे बंगाली रोसगुल्ला खाने से अपने आप को रोके। सड़क किनारे एक बंगाली मिष्ठान की दूकान के बाहर हम सब लोग बंगाली रोसगुल्ला का आनंद लेते हुए खा रहे थे की मेरी दृष्टि कुछ दूर खड़े उन बच्चों पर पड़ी जिनके चेहरे और कपड़ों पर अत्यंत गरीबी झलक रही थी। वो निरंतर हमें देखे जा रहे थे। हमने जैसे ही खाली पत्तों के दोने को कूड़ेदान में फेंक कर छलने लगे तो वो बच्चे तेज़ी से आये और कूड़ेदान से उन दोने पर लगी वासनी को चाटने लगे। इन्हीं देंदर में एक कृता भी कही से आकर उस कूड़ेदान में मूँह मारने लगा। वर्षों बाद भी मैं उस घटना को नहीं भूला हूँ और न ही स्तिथि बदली है। आज भी देश के कई शहरों और गांव में बच्चे से ले कर बजुर्ग भूखमारी के शिकार हो रहे हैं। उन बच्चों की तरह कितने लाखों बच्चे और बड़े बजुर्ग देश में आज भूखे पेट सोते होंगे। आज भी जब मैं कहीं खाने की कोई चीज़ लेता हूँ तो मुझे लगता है उन बच्चों की तरह कितनी ही भूखे चेहरों परा पीछा कर रही है और उनके फैले हुए हाथ और लाचार चेहरों में धसी हुई सिस्तम्बर तक हम हर वर्ष की तरह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं। 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107 देशों में 94 वें स्थान पर है। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली मौतों में से लगभग आधी मौतें कुपोषण के कारण होती हैं, जो की अत्यंत चिंताजनक है। कई देशों में पिछले 18 माह में विश्व में कोरोना महामारी के कारण भूखमारी बढ़ी है। यह चाहे नौकरिया छूट जाने के कारण हो, अनाज की बर्बादी के कारण हो, भूखमारी एक सामाजिक बीमारी है जिससे न केवल समाज में आत्महत्याएं का दर बढ़ा है बल्कि नशा बढ़ा है जिसकी आपूर्ति के लिए अपराध बढ़े हैं। इसके लिए सभी हितधारक - नागरिक समाज, सरकारी ज्ञात्र और शिक्षाविद पोषण के लिए आवश्यक जागरूकता और मांग पैदा करने में मदद करने के लिए एक साथ आगे आना होगा। समय रहते अगर ऐसा नहीं किया गया तो भूखमारी बढ़ेगी। हमारे सारे प्रयास इस दिशा में होना चाहिए की कोई रात को भूखा पेट न सोये कोई भखा पेट न मरे।

